रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

नए भारत की नींव सिद्ध होगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति : कुलपति प्रो. मिश्र

आंतरिक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रकोष्ठ एवं व्यवसायिक अध्ययन एवं कौशल विकास संस्थान द्वारा 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: जिज्ञासा एवं चुनौतियां' पर ऑनलाईन परिचर्चा का आयोजन

जबलपुर 10 सितम्बर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का लागू होना शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक, साहसिक एवं दूरगामी दृष्टिकोण वाला कार्य है। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा रोडमैप भी तैयार किया गया है, जिसमें नीति के सभी प्रावधानों को लागू करने की एक समय सीमा तय की गई है। करीब 75 फीसद प्रावधानों को 2024 तक लागू करने का लक्ष्य है। इसी प्रकार बचे हुए प्रावधान भी वर्ष 2035 तक चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी भी गठित की जाएगी, जो केंद्र और राज्यों के बीच नीति के अमल पर हर साल समीक्षा करेगी। इसमें उल्लेखनीय पक्ष यह है आज हमारा देश ज्ञान–विज्ञान, सूचना–प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कौशल के आधार पर आत्मनिर्भर भारत का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा संकल्पित किया जा चुका है। ऐसे में नई शिक्षा नीति प्रभावी होगी और यह नए भारत की नींव सिद्ध होगी। उपरोक्त विचार माननीय कुलपति प्रो. कपिल देव मिश्र ने गुरूवार को आयोजित ऑनलाईन परिचर्चा के दौरान व्यक्त किए।

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: जिज्ञासा एवं चुनौतियां' विषय पर गूगल मीट के माध्यम से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय आंतरिक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) द्वारा आयोजित ऑनलाईन परिचर्चा में व्यावसायिक अध्ययन एवं कौशल विकास संस्थान के निदेशक प्रो. सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि इस परिचर्चा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में सभी जिज्ञासाओं एवं चुनौतियों को रेखांकित करना है। इन सभी प्रश्नों को माननीय सांसद, जबलपुर एवं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश के द्वारा दिनांक 11 सितम्बर, 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में अपने उद्‌बोधन में सम्भवतः समाहित किया जाएगा। ऑनलाईन परिचर्चा में आईक्यूएसी समन्वयक प्रो. अंजना शर्मा ने बताया कि भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ की शिक्षा नीति बनाने के लिए देश की लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें, 6600 ब्लॉक और 650 जिलों से विचार लिए गए। इसमें शिक्षाविदों, अध्यापकों, अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों एवं व्यापक स्तर पर छात्रों से भी सुझाव लेकर उनका मंथन किया गया। जन आकांक्षाओं के अनुरूप एवं राष्ट्रीय आवश्यकता और चुनौतियों के अनुरूप नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है। इसीलिए जबलपुर में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशिष्ट शिक्षाविद्‌ों के द्वारा अपने विचार और सुझाव रखना महत्वपूर्ण विषय है। ऑनलाईन परिचर्चा का संचालन प्रो. सुरेन्द्र सिंह एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉ. अजय मिश्र ने

किया। इस ऑनलाईन परिचर्चा में संस्कारधानी के विद्वतजन, प्राध्यापक एवं अतिथि विद्वान मौजूद रहे।

ऑनलाईन परिचर्चा में सामने आए ये महत्वपूर्ण सुझाव एवं विचार–

–प्रो. पी.के. बिसेन, कुलपति, जवाहर लाल नेहरू कृषि विवि ने कहा कि 34 वर्ष बाद पुनः राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन किया गया है। यह किसी सरकार की नहीं, बल्कि देश की नीति है। यह नीति 21वीं सदी के आर्थिक भारत को नई दिशा देने वाली है। भारत के सामर्थ्य को आगे बढ़ाने वाली है। कृषि शिक्षा के विद्यार्थी को सभी प्रकार की जानकारी होनी आवश्यक होती है। पारंपरिक अनुसंधान पूर्ण रूप से व्यावहारिक है। कृषि विवि प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसको भी शिक्षा नीति में शामिल करना चाहिए।

–प्रो. एस.पी. तिवारी, कुलपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा एवं विज्ञान विश्वविद्यालय ने कहा कि शिक्षा नीति में बहुत संभावनाएं हैं। स्कूली शिक्षा में जहां सर्वांगींण विकास होगा वहीं उच्च शिक्षा में भी काफी बदलाव आएगा। स्कूलों में इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ेगा। वेटरनरी शिक्षा में 80 प्रतिशत बच्चों को क्लीनिकल जानकारी दी जाती है। 20 प्रतिशत एनिमल संबंधी जानकारी दी जाती है। नई व्यवस्था में छात्रों को क्लीनिकल जानकारी उतनी नहीं मिलती दिख रही है। इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। विशेषज्ञों द्वारा मंथन किया जा रहा है कि नई व्यवस्था के तहत छात्रों को कैसे अधिक से अधिक जानकारी दी जा सके।

–प्रो. बी.एस. चौहान, कुलपति, राष्ट्रीय धर्मशात्र विधि विश्वविद्यालय ने कहा कि शिक्षा नीति तो बेहतर है लेकिन इसको लागू करने में क्या, क्या परेशानियां आएंगी। इस पर मंथन जरूरी है। 1976 के बाद 42वां संशोधन के बाद केन्द्र को भी यह अधिकार मिला कि शिक्षा में वह अपना योगदान दे सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कंप्लीट पैकेज है। पहली आवश्यकता यह है कि एकेडमिक स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। इसमें बहुत ही इनोवेटिव इंस्ट्रक्शन हैं। ये विधिवत लागू हो गए तो कायापलट हो जाएगी।

– ले. जनरल (रिटा.) डॉ. ए.के. मिश्रा, कुलपति मंगलायातन विश्वविद्यालय ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटीज के इश्यु भी इसमें शामिल किए जाने चाहिए। इसमें एक नए भारत के निर्माण की बात है। नए भारत के निर्माण में यह नई शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर साबित होगी। यह शिक्षा नीति ज्ञान–विज्ञान, अनुसंधान नवाचार, प्रौद्योगिकी से युक्त संस्कारक्षम, मूल्यपरक, हर क्षेत्र में, हर परिस्थिति का मुकाबला करने वाली,पूरी दुनिया के लिए भारत में ज्ञान की महाशक्ति के रूप में सामने आएगी। इसमें व्याप्त चुनौतियों और समस्याओं को मंथन द्वारा शुद्ध किया जाना आवश्यक है।

–डॉ. गिरिधर राव, निर्देशक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर ने कहा कि फारेस्ट्री रिसर्च के बारे कुछ इश्यूज को इन्क्लूड करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबलम वार्मिंग के बारे में जानकारी देने का प्रावधान होना चाहिए। मेडिसिनल प्लांटस के बारे में जानकारी शामिल करना चाहिए। इस बारे में नियमित पाठ्यक्रम शुरू होने से छात्रों का ज्ञानवर्धन हो सकेगा। आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। इसको आगे बढ़ाना है। लोगों को जागरूक करने इसका कोर्स शुरू होना चाहिए। देश की जीडीपी में फारेस्ट्री कांस्ट्रीव्यूशन की जानकारी कोर्स में शामिल होनी

चाहिए।

–डॉ. फादर वल्लन अरासू, प्राचार्य, सेंट अलॉयसियस कॉलेज ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रिसर्च, इनोवेशन पर फोकस किया गया है। इसमें बताया गया है कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी निवेश एवं वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा के क्षेत्र में ढांचागत सुधार किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति 2020 में सकल नामांकन को 26.3 फीसद से बढ़ाकर 50 फीसद तक करने का लक्ष्य है, जिसके अंतर्गत उच्च शिक्षा संस्थाओं में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त और भी अनेक प्रावधान किए गए हैं। इन बिन्दुओं के क्रियान्वयन पर मंथन करना आवश्यक है।

–डॉ. टी.एन. दुबे, कुलपति, मप्र आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने कहा कि मेडिकल क्षेत्र की कुछ अलग समस्याएं हैं। नई नीति में छात्रों को मेडिकल के साथ अन्य क्षेत्रों जैसे स्किल, योग आदि के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। प्राइमरी हेल्थ सेंटर का भी उपयोग करने की दिशा में सोचना होगा। बेसिक एजुकेशन पर फोकस करना होगा। बेसिक और आइडियल नॉलेज को बढ़ाना होगा जिसमें हम पिछड़े हुए हैं। ऐसा प्रावधान हो कि के बीएड में मेडिसन कोर्स शामिल हो ताकि हर छात्र, टीचर को सामान्य चिकित्सा के बारे में जानकारी हो सके।

–प्रो. विनीता कौर सलूजा, प्रचार्य, माता गुजरी महिला महाविद्यालय ने कहा कि क्या हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार ने सौ प्रतिशत नामांकन के लिए ऑनलाइन और पत्राचार के जरिए शिक्षा देने का विचार किया है। देश में इंटरनेट और कम्प्यूटर की पहुंच समाज के बड़े तबके तक नहीं है। यहां तक कि सरकार के स्कूलों तक में इनकी उपलब्धता आज तक नहीं सुनिश्चित हो सकी है। ऐसे में सबको ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा देने की बात कल्पनात्मक ज्यादा और यथार्थ कम लगती है।

–प्रो. आर.एस .चंडोक, प्राचार्य, गुरु तेग बहादुर खालसा महाविद्यालय ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत नए कोर्सेस डिजाइन करने होंगे। इसमें बेसिक और प्रायोगिक चीजों को शामिल करना होगा। शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली पर विभाजित किया गया है, तकनीकी शिक्षा, भाषा की बाध्यताओं को दूर करना, दिव्यांग छात्रों एवं महिलाओं के लिए शिक्षा को सुगम बनाने पर बल है, वर्तमान की रटंत एवं बोझिल होती जा रही शिक्षा के स्थान पर रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना के प्रोत्साहन पर बल दिया जाना इसे वर्तमान समय में प्रासंगिक बनाता है। इसके क्रियान्वयन हेतु ईमानदार कोशिशों की आवश्यकता है।

रादुविवि जनसम्पर्क प्रकोष्ठ/क्रमांक/933/10.09.2020